

किफायती मकानों को रफ्तार देने की जुगत चाह रहा रियल्टी उद्योग

राघव अग्रवाल
नई दिल्ली, 28 जून

देश के रियल एस्टेट उद्योग को उम्मीद है कि आगामी बजट में केंद्र सरकार किफायती आवास खंडों के पुनरुद्धार की दिशा में कदम उठाएगी। इस उद्योग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से ऐसी उम्मीद जताई। वैश्विक महामारी कोविड- 19 के बाद से देश के लोगों की प्राथमिकता में बदलाव आया है और अब लोग बड़े और महंगे घरों की तलाश कर रहे हैं, जिससे रियल एस्टेट उद्योग को संघर्ष करना पड़ रहा है।

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक के मुताबिक, भारत में किफायती यानी सस्ते मकानों की बिक्री की हिस्सेदारी साल 2019 के 28 फीसदी से कम होकर इस साल 20 फीसदी रह गई है। कम मांग के कारण ही किफायती मकानों की कुल आपूर्ति भी इस साल घटकर 18 फीसदी हो गई, जो साल 2019 में 40 फीसदी थी। एनारॉक समूह के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, 'भारत के निम्न आय वाले परिवारों की खासतौर से आवास की जरूरतों को ध्यान रखते हुए यह गति सिर्फ महंगे मकानों पर नहीं चल सकती है, जबकि किफायती मकानों में गिरावट जारी है।' उन्होंने कहा कि डेवलपर्स के लिए कर छूट जैसे उच्च प्रभाव वाले उपायों के साथ इस खंड के पुनरुद्धार की जरूरत है ताकि वे किफायती मकानों और खरीदारों पर अधिक ध्यान दे सकें और उनके सामर्थ्य में भी सुधार हो सके। सैटलाइट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड



उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि कीमतों के लिहाज से किफायती मकानों की परिभाषा बदलनी चाहिए

के उपाध्यक्ष (सेल्स, मार्केटिंग एवं सीआरएम) हिमांशु जैन ने कहा कि महानगरों में किफायती मकानों के लिए विशेष योजनाएं शुरू करनी चाहिए और सब्सिडी देनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'नीतियों को मजबूत करने और किफायती मकानों के डेवलपर्स को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने से यह सुनिश्चित होगा कि अधिक से अधिक लोग अपना मकान खरीदने का सपना पूरा कर सकें। महानगरों में जमीन और निर्माण की अधिक कीमत के कारण काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम सरकार से महानगरों में किफायती आवासों के लिए विशेष योजनाएं और सब्सिडी शुरू करने का अनुरोध करते हैं।'

प्रधानमंत्री किसान निधि बढ़ाने की मांग

अर्चिस मोहन
नई दिल्ली, 28 जून

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के मद में आवंटन बढ़ाने सहित कई अन्य सुझाव दिए हैं। इन संगठनों ने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए व्यक्तिगत आय कर घटाने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में भी सुधार का अनुरोध किया है। इन संगठनों का यह भी कहना है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के कारण नौकरी गंवा रहे लोगों को अधिक हुनरमंद बनाने के लिए बजट में 'रोबोट कर' का भी प्रावधान किया जाए।

आएसएस से संबद्ध संस्थाओं जैसे भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती और स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधियों एवं अन्य पदाधिकारियों ने पिछले दो



सप्ताहों के दौरान वित्त मंत्री को अपने सुझाव सौंपे हैं। वित्त मंत्रालय बजट से पूर्व विभिन्न क्षेत्रों एवं संगठनों के साथ चर्चा कर रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच के अश्विनी महाजन ने अन्य अर्थशास्त्रियों के साथ वित्त मंत्री से 19 जून को मुलाकात की थी। उन्होंने प्रोत्साहन संबद्ध योजना (पीएलआई) की सराहना की मगर यह भी कहा कि इसमें अब सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को भी

बजट से उम्मीदें


- **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध संगठनों ने वित्त मंत्री को सौंपे अपने सुझाव**
- **पीएम किसान निधि की राशि बढ़ाने सहित मध्यम वर्ग को कर राहत देने की मांग**
- **संघ से जुड़े संगठनों ने वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में भी सुधार की भी दिया सुझाव**

दिया। बीएमएस ने कहा कि इस रोजगार योजना में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में होने वाले कार्य भी शामिल किए जाने चाहिए। बीएमएस ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का भी सुझाव दिया और केंद्र सरकार में सभी रिक्तियां भरने के लिए तेज से कदम उठाने की मांग की।

भारतीय किसान संघ ने पीएम किसान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाने की मांग की। यह योजना वर्ष 2018-19 में शुरू की

गई थी, जिसका मकसद किसानों को बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है। संघ ने कहा कि केंद्र को सिंचाई के मद में आवंटन बढ़ाने के साथ जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को देखते हुए नदियों को जोड़ने के लिए भी रकम का प्रावधान करना चाहिए। किसान संघ ने कहा कि केंद्र को किसानों को नाम पर कंपनियों को दी जाने वाली 'भारी सब्सिडी' बंद करनी चाहिए क्योंकि सभी किसान इनसे लाभान्वित नहीं होते हैं।

संघ ने कहा कि किसान उर्वरक, औजार एवं बिजली खरीदने के लिए दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। किसान संघ के महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि किसानों को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों एवं औजार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि वे (किसान) उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। मिश्र ने कहा कि या फिर इन्हें जीएसटी मुक्त कर देना चाहिए। लघु उद्योग भारती ने जीएसटी प्रणाली में सुधार के सुझाव दिए।



CIL SECURITIES LIMITED
CIN: L67120TG1989PLC010188
Reg Off: 214 Raghava Ratna Towers, Chirag Ali Lane, Abids, Hyderabad – 500 001
Phone No. 040-2320 3155, Email Id: advisors@cilsecurities.com; Web : www.cilsecurities.com

NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY
NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of CIL Securities Limited (the Company) will be held on Tuesday, 23rd July, 2024 at 12:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and General Circular No. 9/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circular") and Circular No. SEBI/HO/DHMS/P/CIR/2023/0164 dated October 06, 2023 issued by SEBI (in continuation with the Circulars issued earlier in this regard) permits the holding of AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of AGM which is being circulated to the Members of the Company. The Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting"), as provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"), on all resolutions as set out in the Notice of the 35th AGM. All the Members are hereby informed the following:
a) Date and time of commencement of remote e-voting: July 20, 2024 at 10.00 A.M. b) Date and time of end of remote e-voting: July 22, 2024 at 5.00 P.M. c) The Remote E-Voting Module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and the remote E-Voting shall not be allowed beyond the specified period. d) Cut-off / Record date for determining the eligibility to vote: July 15, 2024. Any person, who acquires shares of the Company and becomes the member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off /record date may obtain the login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdsindia.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website. If the member is already registered with CDSL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting. e) Facility for Venue Voting i.e. e-voting during the AGM is also made available at the AGM. Members attending the meeting, who have not already casted their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at/ during the AGM. f) Members who have casted their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be allowed to vote again at the AGM. g) Notice and Annual Report of 35th AGM is available on the Company's website link <http://www.cilsecurities.com/investorRelations.aspx>. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or may contact at 022-23059542/43. h) The Annual Report of the Company for the FY ended March 31, 2024 is placed on the website of the Company, CDSL and on BSE Ltd. i.e. www.cilsecurities.com/ <https://www.evotingindia.com/> and <https://www.bseindia.com/> respectively. **TRANSFER OF SHARES OF THE COMPANY TO DEMAT ACCOUNT OF THE IEPF AUTHORITY** Pursuant to section 124 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, Shares in respect of which the Beneficial Owner has not encashed/claimed any dividend amount during last seven years be transferred to the DEMAT ACCOUNT of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority. Accordingly, the Company have sent a specific communication stating that the shares that are liable to be transferred to DEMAT ACCOUNT of IEPF Authority, to the concerned Shareholders at their latest available address with the Company, who have not claimed the dividend for the Financial Year 2016-17 and for the consecutive seven years upto Financial Year 2023-24 under the said Rules for taking appropriate action(s). The Company has uploaded full details of such Shareholders and Shares due for transfer to DEMAT ACCOUNT of IEPF on its Website: www.cilsecurities.com. Shareholders are requested to refer to the web-link <http://www.cilsecurities.com/investorRelations.aspx> to verify the details of un-encashed/unclaimed dividend and the Shares liable to be transferred to DEMAT ACCOUNT of IEPF. The concerned Shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said Shares along with Dividend(s) from IEPF for which a separate application has to be made to the IEPF in Form IEPF-5, as prescribed under the Rules and the same is available at IEPF Website i.e. www.iepf.gov.in. In case the Company does not receive any communication from the concerned Shareholders by 3rd November, 2024 and the Company shall, with a view to comply with the requirements set out in the Rules, transfer the Shares to the DEMAT ACCOUNT of the IEPF Authority by the due date as per procedure stipulated in the Rules.

For CIL Securities Limited
Sd/-
K K Maheshwari
Managing Director
DIN: 00223241

Date: 28th June, 2024
Place: Hyderabad



MIRZA INTERNATIONAL LIMITED
CIN: L19129UP1979PLC004821
Registered Office: 14/6, Civil Lines, Kanpur-208 001
Tel.: 91-512-2530775 Fax: 91-512-2530166
Website: www.mirza.co.in; E-mail: compliance@mirzaindia.com

NOTICE
(For attention of Equity Shareholders of the Company)
Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority

This notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules") notified by Ministry of Corporate Affairs and amendments made there to. As per Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the aforesaid Rules, all shares in respect of which dividends declared by the Company has not been claimed or remained unpaid for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the IEPF Authority.

In accordance with the various requirements as set out under the aforesaid Rules, the Company has communicated individually to the Shareholders, who have not claimed their dividends for Financial Year 2016-17 and onwards and consequently whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the Financial Year 2024-25, through Speed Post through letter dated June 14, 2024 for claiming such dividends on or before October 3, 2024.

The Company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Authority on its website www.mirza.co.in. Such Shareholders are requested to verify the details of the unclaimed dividend sand shares liable to be transferred to IEPF Authority. The Shareholders who have not claimed their dividends for Financial Year 2016-17 and onwards are requested to claim their dividends expeditiously. In case the Shareholders fails to claim the above unclaimed dividend on or before October 3, 2024, the Company will proceed to transfer the underlying Equity Shares of the Company, registered in the name of the Shareholder to the credit of the IEPF Authority on its due date.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure under the aforesaid Rules, as amended from time to time.

The concerned Shareholders holding shares in physical form may note that the Company would be issuing Duplicate Share Certificate(s) in lieu of the Original Share Certificate(s) held by the Shareholder(s) for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority as per the aforesaid Rules and upon such issue, the Original Share Certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Further, the concerned Shareholders who are holding shares in dematerialized form may note that as per the aforesaid Rules, the Company would be issuing instructions(s) to concerned Shareholder's Depository Participants for the purpose of transfer of their shares to IEPF Authority.

The Shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of the Duplicate Share Certificate(s) by the Company and issuing of instructions(s) to Depository Participants for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority, pursuant to the aforesaid Rules.

In case of any queries, please contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s. KFin Technologies Limited at Selenium, Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, Phone: 040- 67162222 or 18003454001(toll free) or e-mail: einward.ris@kfintech.com.

For Mirza International Limited
Sd/-
(Harshita Nagar)
Company Secretary & Compliance Officer

Date : June 28, 2024
Place : New Delhi

‘वैकल्पिक डेटा स्रोतों का कर रहे इस्तेमाल’

अंजलि कुमारी
मुंबई, 28 जून

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विश्लेषण एवं आर्थिक परख बढ़ाने के लिए वृहद गणना शक्ति और वैकल्पिक डेटा स्रोतों का इस्तेमाल कर रहा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज ये बातें कहीं। दास ने मुंबई में सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित 18वें सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में कहा, 'हमें इस बात का एहसास है कि हम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां सूचनाओं की भरमार है। पहले से संरक्षित डिजिटल डेटा और अधिक से अधिक जानकारी का सुरक्षित भंडार तैयार करने की हमारी क्षमता तेजी से बढ़ रही है। इससे नई चुनौतियां तो सामने आ रही हैं मगर नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं।'

दास ने कहा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे प्रयासों से आर्थिक आंकड़ों के संकलन नए वैश्विक मानक सामने आ सकते हैं। खासकर, राष्ट्रीय खतों एवं भूगोलिक संकेत के मामलों में इस मोर्चे पर अधिक प्रगति होगी। उन्होंने कहा, 'आरबीआई में हमारी टीम इन घटनाक्रम पर नजर रख रही है। हम गणना शक्ति एवं डिजिटल ढांचे के तेज गति से विकास का इस्तेमाल



- **सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में शक्तिकांत दास ने कहा कि हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां सूचनाओं की भरमार है**
- **सुरक्षित भंडार तैयार करने की क्षमता तेजी से बढ़ रही है**
- **इससे नई चुनौतियों के साथ संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे**

विभिन्न मानकों के विश्लेषण के लिए कर रहे हैं। मैं यह जरूर कहूंगा कि वैकल्पिक एवं गैर-परंपरागत डेटा स्रोत कोविड-19 महामारी के कारण लगे पाबंदियों में हमारे लिए काफी उपयोगी साबित हुए।'

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि डेटा स्रोतों के साथ रफ्तार बनाए रखने के लिए डेटा प्रबंधन प्रणाली को लगातार प्रगति करनी होगी। उन्होंने कहा कि इनमें आंकड़ों की भरमार के बीच सटीक तरीके से नियमित अंतराल पर मिलने वाले संकेतकों को अलग करने होंगे।

एचडीएफसी लाइफ से कर मांग

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने शुक्रवार को कहा कि उससे आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विभाग ने 1,495.17 करोड़ रुपये की कर मांग की है। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि इसमें ब्याज के तौर पर 592.41 करोड़ रुपये की मांग भी शामिल है। कर अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ने नेगेटिव रिजर्व को कर योग्य अधिशेष का हिस्सा नहीं माना था और शेषधारकों की शुद्ध निवेश आय को अन्य स्रोतों से आय के बजाय जीवन बीमा व्यवसाय से आय के रूप में वर्गीकृत किया। बीएस

मई में प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि घटी

आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योग, जिन्हें कोर सेक्टर या प्रमुख क्षेत्र भी कहा जाता है, के उत्पादन में वृद्धि अप्रैल के 6.7 फीसदी से कम होकर मई में 6.3 फीसदी रह गई। महीने के दौरान छह क्षेत्रों के उत्पादन में आई गिरावट के कारण ऐसा हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई महीने में प्राकृतिक गैस (7.5 फीसदी), रिफाइनरी उत्पाद (0.6 फीसदी) और इस्पात (7.6 फीसद) जैसे क्षेत्रों के उत्पादन की वृद्धि दर घटी है।

मई में उर्वरक (-1.7 फीसदी) और सीमेंट (-0.8 फीसदी) जैसे

क्षेत्रों के उत्पादन में और गिरावट आई। मई में कच्चे तेल (-1.1 फीसदी) के उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी ओर, कोयला (10.2 फीसदी) और बिजली (10.8 फीसदी) का उत्पादन मई में बढ़ा है।

पिछले साल मई में प्रमुख क्षेत्र ने 5.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की थी। वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीनों में प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि 6.5 फीसदी रही। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2024 में आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की वास्तविक वृद्धि दर 7.1 फीसदी थी। बीएस

बीएस सूडोकू 5012

		8		6	4
	7	9			
4		2			
1			2		7
7					5
	5	4	7		3
5		7		1	6
		5			3
6					8

परिणाम संख्या 5011

7	6	1	3	9	8	4	2	5
9	2	3	4	7	5	6	8	1
4	5	8	2	1	6	9	7	3
3	9	2	6	4	1	7	5	8
8	4	6	5	3	7	2	1	9
5	1	7	8	2	9	3	4	6
6	7	9	1	5	4	8	3	2
2	8	5	7	6	3	1	9	4
1	3	4	9	8	2	5	6	7

कैसे खेलें ?

हर रोज, कॉलम और 3 के बाईं 3 के बाँक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

बहुत आसान

★☆☆☆☆

डिस्क्लेमर.. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और संस्थाओं से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के निबंधन एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भावना में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बिना समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

UNSETTLED AT IIT

With the rise of the ‘unplaced’, getting into an IIT no longer guarantees a good career. What is the way out?

AHONA CHAKRAVARTY
New Delhi, 28 June

Across coaching centres as well as homes of adolescents, an often-heard war cry is: “*Ek bar IIT chale jao, life set hai* (once you join an IIT, you are guaranteed a good life).” Right now, many would be questioning that.

Getting into an Indian Institute of Technology (IIT) is not easy. Of the 1,415,110 students who appeared in the JEE-Main 2024, less than 2 per cent would find a seat. The IIT acceptance rate is said to be lower than that of the famed MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA).

But now, in a turn of events, passing out of the IITs is not proving to be a cake-walk for everyone. Thousands are struggling to find jobs in campus placements.

At the end of May, Dheeraj Singh, who holds a chemical engineering degree from IIT Kanpur, filed a Right to Information (RTI) application seeking placement data for the last three academic years from IIT Kharagpur. On June 12, the institute replied: In 2021-22, of the 2,256 who registered for placement, 1,615 were placed, which works out to 71.5 per cent. In 2022-23, of the 2,490 who registered, 1,675 — 67.2 per cent — were placed. And last year, 2023-24, 1,564 were placed out of the 2,660 who registered — falling further to 58.7 per cent. The placement process was still going on when the reply came.

“Please note that typically 75 per cent of the graduating students register for placements in IIT Kharagpur and the remaining pursue other options, such as higher studies, entrepreneurship, civil services, etc,” Singh told *Business Standard*.

He had sought similar data through RTIs from the other IITs as well and says nearly 40 per cent of the IITians sitting for placements in 2024 are yet to

receive job offers, showing a doubling of the ‘unplaced’ in the last three years from 19 per cent in 2021-22 to 38 per cent in 2023-24.

Unsurprisingly, perhaps, there is a parallel dampening of salaries. “Entry level salaries are not what they used to be,” says Ramesh Alluri Reddy, Chief Executive Officer, TeamLease Degree Apprenticeship.

Singh recalls the hype around the crore-plus packages offered at IITs that made headlines, and says: “The reality is that the median package has gone down by 15 to 20 per cent.”

A student at IIT Delhi says many of his mates on the campus are worried. Even people who are placed or have received pre-placement offers fear that their offers might get revoked — this has happened before.

So, why is it that thousands of IITians are not “set for life”?

Global economy, AI

Experts say a big reason is the macro-economic condition.

“There is a slowdown in the global economy, there is this war situation, and everything is so volatile right now,” says Reddy.

Singh, who filed the RTIs, says that due to the higher interest rates, particularly in the United States, and the higher inflation, companies are focusing more on profitability than growth. “They are certainly reducing their headcount, which is the first expense they want to optimise on,” he says.

Another reason is the over-hiring by tech firms during the COVID-19 pandemic, when technology was seen to be in an endless phase of boom. Reddy says this resulted in high attrition. Companies also started restructuring.

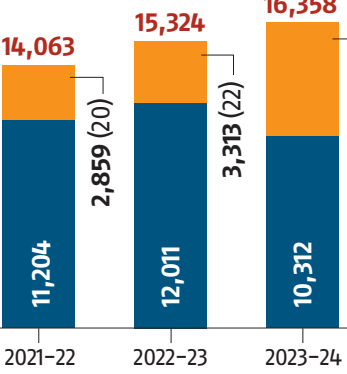
Purnendra Kishore, who studied at IIT-BHU and spent years in the education sector, says information technology firms, the biggest recruiters at IITs,



IIT PLACEMENT TREND

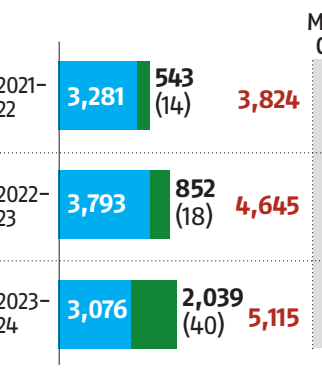
Older IITs

■ Placed ■ Unplaced ■ Registered
Figures in brackets:
% unplaced



Newer IITs

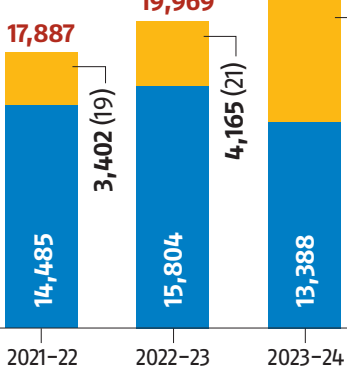
■ Placed ■ Unplaced
■ Registered
Figures in brackets: % unplaced



Note: These are session years
CTC: Cost to company, LPA: Lakh per annum
Source: RTI filed by Dheeraj Singh, an IIT Kanpur graduate

All IITs

■ Placed ■ Unplaced ■ Registered
Figures in brackets:
% unplaced



were caught between a large employee base and falling demand. “These firms had been the mass recruiters, and when they went missing, the situation worsened,” he adds.

Another factor is the adoption of artificial intelligence (AI). Its sudden ramp-up has affected software engineering jobs the most, leading to a sharp drop in job offers.

On the bright side, according to a study by the International Labour Organisation, generative AI is more likely to enhance jobs by automating specific tasks, rather than replacing entire roles. The report states that most jobs are only partly susceptible to automation.

Need to upskill

Singh says the pace of automation is so fast due to AI that recruiters no longer require to hire for the low-end jobs. For example, currently there is demand for AI learning skill sets, but openings for web developers has decreased across firms.

Companies are making significant changes to their business models, hiring for specific functions or skill sets, and students are not able to cope with the pace of change. “Students in software engineering courses do not know the skills of a prompt engineer, which is crucial now,” says Reddy.

Traditionally, IT, engineering, consulting, and finance companies have pre-

dominantly hired from IITs. This is changing, with a rise in hiring by manufacturing and semiconductor companies, and global capability centres, or GCCs. In addition, the electric vehicles industry is poised to create a large number of direct and indirect jobs. So are the drones industry and National Green Hydrogen Mission. There is an anticipated surge in demand for roles in chip design, cybersecurity, machine learning, and user experience design.

But it will take special efforts to grab some of those jobs.

According to Deloitte Campus Workforce Trends 2024, more firms are now shifting towards hiring based on skills. For example, artificial intelligence

and machine learning jobs in engineering, social selling in management, and computational biology in pharma are the most in-demand segments.

“Campus hiring this year is witnessing a mild slowdown... companies are preferring experienced candidates over freshers. Campus compensation for the top 10 colleges, including IITs, has witnessed a marginal decline for the first time in the last five years...,” says Neelesh Gupta, Partner, Deloitte India. “AI, machine learning, cyber security, computational dynamics, robotics, mechatronics and control systems, and ESG Tech are the top skills which are commanding a 10 to 15 per cent pay premium in campuses.”

Hope floats on campuses

Coaching institutes across the country witnessed a steep drop in intake during the pandemic due to limited social access. Prominent coaching institutes saw a decline in admissions by 30 to 35 per cent. But, as the economy opened up, admissions surged, and continue unabated in spite of the rise of the unplaced.

Kishore says several of those enrolling in Kota and other coaching hubs come from small towns. “They are awed by the dream of going to an IIT. It is hard for them to analyse the recent developments,” he adds.

In the large metros, young people talk about several career options, but in the smaller towns the options are largely engineering, medicine, and other conventional paths.

Singh says there is need for an employment data system for the country. “The Reserve Bank of India, before its monetary policy, should be able to look at the employment indicators, just like the Fed in the US does before deciding the interest rates. That’s a huge input for the industry to kickstart investments and the growth cycle,” he adds.

Reddy says there needs to be at least six months to a year of practical on-the-job training as part of the course. Institutes should also introduce more vocational courses.

But there is hope. At IIT Patna, 72 per cent of the registered candidates are already placed and the process is underway for others. “We expect a decent improvement in the statistics till June 2024,” says Kripa Shankar Singh, Training and Placement Officer, at the institute.

He adds that upskilling is an important step the institute has taken to meet recruiters’ expectations.

Emails and messages sent to other IITs elicited no response till the time of going to press.

Markets,
Monday to Saturday

To book your copy,
sms
reachbs
to **57575** or
email **order@bsmail.in**

50
Years of insight

Business Standard

श्री अशोक

Bank of Maharashtra

बँक ऑफ महाराष्ट्र

Head Office : Lokmangal, 1501,
Shivajinagar, Pune-411005.

Notice Inviting Tender (RFP)

Bank of Maharashtra invites sealed tender offers (Technical bid and Commercial bid) from eligible and reputed bidders /service providers for “**RFP-15/2024-25 for Appointment of Consultant for Migration Services of Certification from ISO 27001:2013 to ISO 27001:2022 of the Bank.**”
The detailed tender document is available on tender section of Bank's website: <https://www.bankofmaharashtra.in> and Govt. e-Market place (GeM) portal <https://gem.gov.in/> w.e.f. 28/06/2024 with following details:
GeM Bid No: GEM/2024/B/5100578 dated 28/06/2024
Due date for Bid submission: 15/07/2024
All further updates related to tenders will also be available on Bank's website. Bank reserves the right to cancel or reschedule the RFP process without assigning any reason.
Date : 28/06/2024

Sd/-
Chief Information Officer

MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L19129UP1979PLC004821
Registered Office: 14/6, Civil Lines, Kanpur208 001
Tel.: 91-512-2530775 Fax: 91-512-2530166
Website: www.mirza.co.in; E-mail: compliance@mirzaindia.com

NOTICE

(For attention of Equity Shareholders of the Company)

Transfer of Equity Shares of the Company to the
Demat Account of Investor Education and Protection Fund (“IEPF”) Authority

This notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (“Rules”) notified by Ministry of Corporate Affairs and amendments made there to. As per Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the aforesaid Rules, all shares in respect of which dividends declared by the Company has not been claimed or remained unpaid for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the IEPF Authority.

In accordance with the various requirements as set out under the aforesaid Rules, the Company has communicated individually to the Shareholders, who have not claimed their dividends for Financial Year 2016-17 and onwards and consequently whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the Financial Year 2024-25, through Speed Post through letter dated June 14, 2024 for claiming such dividends on or before October 3, 2024.

The Company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Authority on its website www.mirza.co.in. Such Shareholders are requested to verify the details of the unclaimed dividend and shares liable to be transferred to IEPF Authority. The Shareholders who have not claimed their dividends for Financial Year 2016-17 and onwards are requested to claim their dividends expeditiously. In case the Shareholders fails to claim the above unclaimed dividend on or before October 3, 2024, the Company will proceed to transfer the underlying Equity Shares of the Company, registered in the name of the Shareholder to the credit of the IEPF Authority on its due date.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure under the aforesaid Rules, as amended from time to time.

The concerned Shareholders holding shares in physical form may note that the Company would be issuing Duplicate Share Certificate(s) in lieu of the Original Share Certificate(s) held by the Shareholder(s) for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority as per the aforesaid Rules and upon such issue, the Original Share Certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Further, the concerned Shareholders who are holding shares in dematerialized form may note that as per the aforesaid Rules, the Company would be issuing instructions(s) to concerned Shareholder's Depository Participants for the purpose of transfer of their shares to IEPF Authority.

The Shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of the Duplicate Share Certificate(s) by the Company and issuing of instructions(s) to Depository Participants for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority, pursuant to the aforesaid Rules.

In case of any queries, please contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s. KFin Technologies Limited at Selenium, Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, Phone: 040- 67162222 or 18003454001 (toll free) or e-mail: einward.ris@kfintech.com.

For Mirza International Limited
Sd/-
(Harshita Nagar)
Company Secretary & Compliance Officer

Date : June 28, 2024
Place : New Delhi

HEG LIMITED

CIN : L23109MP1972PLC008290

Regd. Off.: Mandideep (Near Bhopal), Distt. Raissen-462046, (M.P.); Phone: 07480-233524, 233525, Fax: 07480-233522
Corp. Off.: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida-201301 (U.P.); Phone: 0120-4390300 (EPABX); Fax: 0120-4277841
E-mail: heg.investor@lnjbhilwara.com; Website: www.hegltd.com

NOTICE OF 52nd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

In continuation to our newspaper advertisement dated 26th June, 2024, Notice is hereby given that **52nd Annual General Meeting ('AGM') of HEG LIMITED ('the Company') will be held on Wednesday, 7th August, 2024 at 2:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM')** without physical presence of members at the AGM venue to transact businesses as set out in the notice of AGM. The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Mandideep (Near Bhopal), Distt. Raissen-462 046, Madhya Pradesh.

The Ministry of Corporate Affairs ('MCA') vide its General Circular no. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 and other relevant circulars ('MCA Circulars'), has permitted the holding of the AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. Further, SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October 2023 ("SEBI Circular"), has granted relaxation in respect of sending physical copies of the Annual Report to shareholders and requirement of proxy for general meetings held through electronic mode.

In terms of the said MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 52nd AGM and the Annual Report of the Company including standalone and consolidated financial statements for the financial year 2023-24 along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 28th June, 2024 through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s).

The Annual Report and Notice of 52nd AGM are also available on the Company's website i.e. www.hegltd.com, websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL), appointed by the Company for providing remote e-voting / e-voting facility at the AGM at www.evoting.nsdl.com.

Further, Members may directly access the Annual Report for FY 2023-24 at the following link:
<https://hegltd.com/wp-content/uploads/2024/06/HEG-AR-2024-Spread.pdf>
Members may further note that:

- The businesses set out in the notice of AGM, will be transacted through remote e-voting or e-voting facility at the AGM.
- The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. **Wednesday, 31st July, 2024**. A person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM and a person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, 1st August, 2024 to Wednesday, 7th August, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and for payment of final dividend for FY 2023-24, if declared at AGM.
- The Members, whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on **Wednesday, 31st July, 2024**, i.e. the date prior to the commencement of book closure, will be paid the Final Dividend of Rs.22.50 per Equity Share of the face value of Rs.10 each for the financial year 2023-24, as recommended by the Board, if declared at the 52nd AGM of the Company, within 30 days from the date of AGM.
- The notice of AGM inter-alia includes the process and manner of remote e-voting/e-voting and instructions for participation in the AGM.
- The remote e-voting period commences on **Saturday, 3rd August, 2024 (9:00 a.m.) and end on Tuesday, 6th August, 2024 (5:00 p.m.)**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Electronic Voting Even Number (EVEN): 129047

Any person who acquires shares and become member of the Company after dispatch of notice and holding shares as on cut-off date i.e. **Wednesday, 31st July, 2024** may obtain login Id and password by sending a request over email at evoting@nsdl.com mentioning demat account number/folio number, PAN, name and registered address. However Members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User id and Password for casting their vote through remote e-voting/e-voting at the AGM.

Manner of voting for members holding shares in physical form, dematerialized form or who have not registered their e-mail address with the Company is provided in the Notice of AGM, which is also available on the website of the Company at www.hegltd.com.

The facility of e-voting shall be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in the notice of AGM. Further members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to vote at the AGM.

Mr. Saket Sharma, a Practicing Company Secretary (Certificate of Practice No. 2565, Membership No. FCS 4229), Partner, M/s. GSK & Associates has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the meeting by posting the same on the website of the Company (www.hegltd.com), website of NSDL (www.evoting.nsdl.com) and by filing with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office & Corporate Office of the Company. Subject to the requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the AGM i.e. **7th August, 2024**.

Members who have not registered their email-id and/or Bank details are requested to register the same by following the procedure given below:

Shareholders with Physical Holding

Shareholders have to fill the Form ISR-1 and other forms for updating their Email address / Mobile no. / Bank Account particulars and other details, if yet not updated by them, and send the same duly completed in all respect to the **RTA of the Company i.e. MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: HEG Limited), F-65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020**, Phone no. 011-41406149-52. The said forms can be downloaded from the website of the Company i.e. www.hegltd.com under head **Investors > Investor Service Request > Updation of PAN, KYC, Nomination and Bank Account Details etc.**

Shareholders with Demat Holding

- Please contact your Depository Participant (DP) and register your Email address / Mobile No. / PAN / Bank Account particulars in case the same are yet not updated in your demat account, as per the process advised by your DP.
- In case Email address / Mobile No. are updated but presently you have Opted for “email RTA download flag as “No” in your demat account, you can contact your DP for email download flag as “Yes” so that you can be able to receive the various communication sent through email by the Company. OR you can ask your DP to make necessary updation in your demat account so that in future you can be able to get Annual Report / Notice / various communications from the Company in electronic mode.

Members may note that the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company on or after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making the final dividend, if declared at the ensuing AGM. The withholding tax rate would vary depending on the residential status, category of the shareholder and is subject to provision of requisite declarations / documents provided by the concerned shareholder to the Company.

In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 **before 31st July, 2024**. Please note that the Company had vide its e-mail communication dated 11th June, 2024 and also by way of newspaper advertisement informed the Members regarding this change in the Income Tax Act, 1961 as well as the relevant procedure to be adopted by the Members to avail the applicable tax rate. *For more details, kindly refer the note no. 26 of the Notice of AGM relating to Dividend TDS communication. The copies of same is also available on the website of the Company i.e. www.hegltd.com.*

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.com. In case of any grievance connected with facility for remote e-voting or e-voting, please contact to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, MUMBAI - 400 013 at the designated email id: evoting@nsdl.com.

For HEG Limited
Sd/-
Vivek Chaudhary
Company Secretary
A-13263

Place: Noida (U.P.)
Date : 28th June, 2024